



७

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

बसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 269]

नई विल्सी, सोमवार, अगस्त 20, 1979/भाषण 29, 1901

No. 269]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 1979/SRAVANA 29, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सर्वा दो जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवेहन एवं परिवेहन मन्त्रालय

(परिवेहन पक्ष)

प्रधिसूचनाएं

नई विल्सी, 20 अगस्त, 1979

सं० का० नि० 502 (ग्र).—कलकत्ता पत्रक का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) मंशोधन नियम, 1979 का एक प्रारूप, महावित्तन न्यास प्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार, भारत मंत्रालय के नौवेहन और परिवेहन मन्त्रालय (परिवेहन पक्ष) की प्रधिसूचना सं० सा० का० नि० 399 (ग्र), नारीख 25 जून, 1979 के प्रशीन भाग के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3 (1), नारीख 25 जून, 1979 के पृष्ठ 869-870 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें राजपत्र में उक्त प्रधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी अवधियों से आपत्तियाँ और मुकाबल मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 3 जुलाई, 1979 को जनना की उपलब्ध करा दी गयी थी।

और जनना से पूर्वोत्तम प्रबंधि की वकाएत के पर्यंत कोई आपत्तियाँ/मुकाबल प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः, अब, केंद्रीय मंत्रालय उक्त प्रधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

नियम

1 (1) इन नियमों का नाम कलकत्ता पत्रक का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होने।

2. कलकत्ता पत्रक का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 में, नियम 4 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्—

“5. जो न्यासी संसद भवस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना।—

नियम 2 और 3 में कुछ भी कहे जाने के बाबजूद कोई भी न्यासी जो संसद अथवा राज्य विधायिका का भी सदस्य हो, संसद (निर्देशना निवारण) प्रधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में धर्यापरिभासित प्रतिपुरक भत्ते को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हों तो, जिन्हें राज्य विधायिका का सदस्य इस प्रकार की

निर्देशन के बिना राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए निर्देशन निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो, अन्य किसी भी शुल्क का हक्कदार नहीं होगा।'

[सं. पी. जी. एल. 17/79]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 20th August, 1979

G.S.R. 502 (E).—Whereas the draft of the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979, was published as required by sub-section (2) of Section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at page 869-70 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 (i), dated the 25th June, 1979, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 399 (E), dated the 25th June, 1979, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And Whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd July, 1979;

And Whereas no objections and suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the said Act, the Central Government hereby make the following rules, namely:—

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:—

"5. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State.—Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a Member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification."

[F. No. PGL-17/79]

का० का० नि० 503 (म)—बम्बई पत्तन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अवायगी) संगोष्ठन नियम, 1979 का एक प्राप्त, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार, भारत सरकार के मोनहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिकृता सं. का० का० नि० 400 (म), तारीख 25 जून, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, ए४ (3) (1), तारीख 25 जून, 1979 के पृष्ठ

870 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें राजपत्र में उक्त अधिकृता के प्रकाशन की तारीख से वैतालीम दिन भी अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आपलिया और मुझाव मनि गए हैं, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र की प्रतिया 3 जूनार्द, 1979 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं।

मैर जनता में पूर्वोंक अवधि की समाप्ति के पूर्व कोई आपलिया/मालाक प्राप्त नहीं हए हैं।

अत अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के द्वारा प्रवत्त व्यक्तियों का ग्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम जनता है, अधिनि.—

नियम

1. (1) इन नियमों का नाम बम्बई पत्तन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अवायगी) संगोष्ठन नियम, 1979 है।

(2) ये गजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होगे।

2. बम्बई पत्तन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अवायगी) नियम, 1975 में, नियम 243 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अधिनि:—

5. जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधायिका का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अवायगी करना:—

नियम 2 और 3 में कुछ भी कहे जाने के बाबजूद कोई भी न्यासी जो संसद अथवा राज्य विधायिका का भी सदस्य हो संसद (निर्देशन निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के ए४ (क) में यथापरिसाधित प्रतिवृत्त भत्ते को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हक्कदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हों तो, जिन्हें राज्य विधायिका का सदस्य हस प्रकार की निर्देशन के बिना राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए निर्देशन निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो, अन्य किसी भी शुल्क का हक्कदार नहीं होगा।"

[सं. पी. जी. एल. 17/79]

G.S.R. 503 (E).—Whereas the draft of the Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979, was published as required by sub-section (2) of Section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at page 870 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i), dated the 25th June, 1979, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 400 (E), dated the 25th June, 1979, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd July, 1979;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the said Act, the Central Government hereby make the following rules, namely:—

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

“5. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State.— Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a Member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowance, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.”

[F. No. PGL-17/79]

सा० का० नि० 504 (अ).—मद्रास पतन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 का एक प्रारूप, महापतन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 की धारा 122 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 401 (अ), तारीख 25 जून, 1979 के प्रयोग भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3 (1), तारीख 25 जून, 1979 के पृष्ठ 871 पर प्रकाशित किया गया था, जिस में राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पंतलीस दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आपत्तिया और सुकाव भागें गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 3 जुलाई, 1979 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं।

और जनता से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कोई आपत्तिया/सुकाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः प्रब, फेन्ड्रोय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

मियम

1. (1) इन नियमों का नाम मद्रास पतन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन, नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होने।

2. मद्रास पतन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 में, नियम 2 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“3. जो न्यासी मंडल मदस्त हो या गज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना :—

नियम 2 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो सदस्य गज्य विधायिका का भी सदस्य हो, समर (निर्वहन निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभासित प्रतिपूर्वक भत्त को छोड़कर, उसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का लकड़ार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हों तो, जिन्हें गज्य विधायिका का सदस्य हस प्रकार की निर्वहन के बिना गज्य विधायिका की सदस्यता के निए निर्वहन निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के प्रधीन प्राप्त करता हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकड़ार नहीं होगा।”

[सं० पी० जी० एल०-17/79]

G.S.R. 504(E).—Whereas the draft of the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979, was published as required by sub-section (2) of Section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at page 871 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i), dated the 25th June, 1979, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 401(E), dated the 25th June, 1979, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd July, 1979;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the said Act, the Central Government hereby make the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975 after rule 2, the following rule shall be inserted, namely :—

“3. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State.— Notwithstanding anything contained in rule 2, a Trustee who is also a Member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowance, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.”

[F. No. PGL-17/79]

सा० का० नि० 505(अ).—पूर्नोकोरित पतन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 का एक प्रारूप, महापतन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 402 (अ), तारीख 25 जून, 1979 के प्रधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3 (1), तारीख 25 जून, 1979 के पृष्ठ 871-872 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पंतलीस दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आपत्तिया और सुकाव भागें गये थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र को प्रतियां 3 जुलाई, 1979 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं।

और जनता से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कोई आपत्तिया/सुकाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः यद्य, केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, प्रथात्:—

नियम

1. (1) इन नियमों का नाम नूसीकोरिन पत्तन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों को अदायगी) संशोधन नियम 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होने।

2. नूसीकोरिन पत्तन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1979 में, नियम 3 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, प्रथात्:—

“4. जो न्यासी संसद सदस्य हों या राज्य विधान सभा का सदस्य हों, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना।—

नियम 2 और 3 में कुछ भी कहे जाने के बाबजूद कोई भी न्यासी जो संसद प्रथा राज्य विधायिका का भी सदस्य हो, संसद (निरहुता निवारण) प्रधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित प्रतिपूरक भत्तों को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हक्कदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हो तो, जिन्हे राज्य विधायिका का सदस्य इस प्रकार को निरहुता के बिना राज्य विधायिका को सदस्यता के लिये निरहुता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के मध्यम प्राप्त करता हो, अन्य किसी भी शुल्क का हक्कदार नहीं होगा।”

[सं पों जो०एल०-17/79]

G.S.R. 505(E).—Whereas the draft of the Board of Trustees of the port of Tuticorin (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979, was published as required by sub-section (2) of Section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at pages 871-872 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i), dated the 25th June, 1979, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 402(E), dated the 25th June, 1979, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd July, 1979;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the said Act, the Central Government hereby make the following rules, namely:—

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Tuticorin (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Tuticorin (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1979, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:—

“4. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State.—Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a Member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification)

Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.”

[F. No. PGL-17/79]

सांख्यिकी 506(अ).—मार्मगांग न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 का एक प्रस्तुत महापत्तन स्थान प्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार, भारत सरकार के नोवेल और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं ३० सांख्यिकी 403(अ), तारीख 25 जून, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3(1), तारीख 25 जून, 1979 के पृष्ठ 872 पर, प्रकाशित किया गया था, जिसमें राजपत्र में उक्त प्रधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैमाली संवित की अवधि की समाप्ति तक उस सभी व्यक्तियों से प्राप्तियां और सुझाव भागे गए थे, जिनके उससे पाम उसने प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र की प्रतिधा 3 जुलाई, 1979 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी।

और जनता से पूर्वोक्त प्रधिसूचना की समाप्ति के पूर्व कोई प्राप्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः यद्य, केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के अनुराग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, प्रथात्:—

नियम

1. (1) इन नियमों का नाम मार्मगांग न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होने।

2. मार्मगांग न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1964 में, नियम 4 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, प्रथात्:—

“5. जो न्यासी संसद सदस्य हों या राज्य विधान सभा का सदस्य हों, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना।—

नियम 3 और 4 में कुछ भी कहे जाने के बाबजूद कोई भी न्यासी जो संसद प्रथा राज्य विधायिका का भी सदस्य हो, संसद (निरहुता निवारण), प्रधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित प्रतिपूरक भत्तों को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हक्कदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हो तो, जिन्हे राज्य विधायिका का सदस्य इस प्रकार की निरहुता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के मध्यम प्राप्त करता हो, अन्य किसी भी शुल्क का हक्कदार नहीं होगा।”

[सं पों जो०एल०-17/79]

G.S.R. 506 (E).—Whereas the draft of the Mormugao Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979, was published as required by sub-section (2) of Section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at page 872 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i), dated the 25th June, 1979, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 403 (E), dated the 25th June, 1979, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd July, 1979;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the said Act, the Central Government hereby make of the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Mormugao Port Trust Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mormugao Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:—

“5. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State.—Notwithstanding anything contained in rules 3 and 4, a Trustee who is also a Member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.”

[F. No. PGL-17/79]

सांकेतिक 507(प्र) :- पारावीप न्यासी मंडल (न्यासियों को जुहक और भल्तों की अवायरी) संशोधन नियम, 1979 का एक प्रारूप, महाप्रत्नन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) के अधिकानुसार, भारत सरकार के नौबहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं १०२००.०५० 404, तारीख 25 जून, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र धारा 2, खण्ड 3(1), तारीख 25 जून, 1979 के पृष्ठ 872-873 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैतारीम विन की अवधि की समाप्ति तक उन उभी व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुकाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ।

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 3 जूसाई, 1979 को अमना को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और जनता से पूर्वोक्त अधिकारी की समाजिक से पूर्व कोई आपत्तिया/ सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रतः अब, केन्द्रीय भरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के व्यापार प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम घनाती है, प्रथाः—

नियम

- (1) इन नियमों का नाम पारार्द्धप्रायासी मंडल (च्यासियों की शुल्क और भत्तों की अवधारणी) संशोधन नियम, 1979 है।
- (2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पारावीय न्यायी मंडल (न्यायियों की शुल्क और भस्तों की श्रद्धावानी) नियम, 1967 में, नियम 3 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, प्रत्यापत्ति:—

“4. जो न्यासी संसद भवस्य हो आ राज्य विधान मभा का भवस्य हो, उसे छुल भत्तों की अदायगी करना:—

नियम 2 और 3 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यायी जो संसद अथवा राज्य विधायिका का भी सदस्य हो, संसद (निरंहता निवारण) प्रधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के अप्प (क) में अधारिभाषित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शालक का तृकदार नहीं होगा, या उन भर्तों को छोड़कर यदि कोई हो तो, जिन्हें राज्य विधायिका का सदस्य हम प्रकार की निरंहता के बिना राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए निरंहता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लाना किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो, अन्य किसी भी शालक का तृकदार नहीं होगा ।”

ਸੰ. ੴ. ਜੀ. ਅਨੁ. 17/791

G.S.R. 507 (E) :—Whereas the draft of the Paradip Port-Trust, (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979, was published as required by sub-section (2) of Section 122 of the Major Port Trusts, Act, 1963 (38 of 1963) at page 872-73 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i), dated the 25th June, 1979, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G. S. R. 404 (E), dated the 25th June, 1979, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd July, 1979;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Paradip Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the *Official Gazette*.

2. In the Paradip Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1967 after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:—

"4. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State.—Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a Member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowances as defined in clause (a) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification."

[F. No. PGL-17/79].

सांख्यिकी 508(अ) :—महापत्तन न्यास (न्यासियों की शुल्क और भत्तों की अवायी) संशोधन नियम, 1979 का एक प्रारूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार, भारत सरकार के नौबहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सांख्यिकी 405 (अ), तारीख 25 जून, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3(i), तारीख 25 जून, 1979 के पृष्ठ 873 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की नारीख से वैतालीक दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी अधिकारियों से आपत्तियां और सुकान मांगे गये थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 3 जुलाई, 1979 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं।

और जनता से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कोई आपत्तियां / सुकान प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रत. अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (i) के द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, प्रथात् :—

नियम

1. (1) इन नियमों का नाम महापत्तन न्यास (न्यासियों की शुल्क और भत्तों की अवायी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रृष्ठ होंगे।

2. महापत्तन न्यास (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अवायी) नियम, 1964 में, नियम 4 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, प्रथात् :—

“3. जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अवायी करना :—

नियम 3 और 4 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद पर्यावरण राज्य विधायिका का भी सदस्य हो, संसद (निरंहता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (k) में यथापरिभावित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जेंडी भी स्थित ही, अप्प किसी भी शुल्क का हक्कदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हो तो, जिन्हें राज्य विधायिका का सदस्य इस प्रकार की निरंहता के बिना राज्य विधायिका की सदस्यता के लिये निरंहता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय सामू किसी भी कानून के प्रधीन प्राप्त करता हो, अप्प किसी भी शुल्क का हक्कदार नहीं होगा।”

[मं० पी०जी०एल० 17/79]

G.S.R. 508(E).—Whereas the draft of the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979, was published as required by sub-section (2) of Section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at page 873 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i), dated the 25th June, 1979, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 405(E), dated the 25th June, 1979, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd July, 1979;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the said Act, the Central Government hereby make the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

“5 Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State.—Notwithstanding anything contained in rules 3 and 4, a Trustee who is also a Member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.”

[F. No. PGL-17/79]

सांख्यिकी 509(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उसी धारा की उपधारा (i) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) द्वारा प्रवक्ता प्रवित्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मद्रास पत्तन के न्यासियों के मछली में श्री एम० कल्याणसुन्दरम, संसद सदस्य को न्यासी के स्वयं में, जो मद्रास पत्तन में कार्यरत अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौबहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सां० का० निय० 302(ई), दिनांक 31 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, प्रथात् :—

उक्त अधिसूचना में, कम संख्या 17 के बाद निम्नलिखित कम संख्या और प्रवित्ति रखी जाए, प्रथात् :—

“18. श्री एम० कल्याणसुन्दरम, संसद सदस्य : पत्तन में कार्यरत अधिकारियों के प्रतिनिधि।”

[काइल सं० पीटीवी-43/78]

G.S.R. 509.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoint Shri M. Kalyanasundaram, M.P., as trustee, representing the labour employed in the Port of Madras, on the Board of Trustees of the Port of Madras, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 302(E), dated the 31st March, 1979, namely :—

In the said notification, after Serial Number 17, the following Serial Number and entry shall be inserted, namely :—

“18. Shri M. Kalyanasundaram, M.P.—Representing the labour employed in the Port.”

[F. No. PTB-43/78]

गा० का० नि० 510 (ए).—महापालन न्यास प्रशिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उसी धारा की उपधारा (i) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार कोचीन पत्तन के न्यामियों के खण्ड में श्री वयालार रवि, संसद मवस्य को न्यामी के रूप में, जो कोचीन पत्तन में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नियुक्त करती है और भारत मरकार के नौकरहन और परिवहन मंवालय (परिवहन एक्ष) की अधिसूचना संख्या का० नि० 304(ई), दिनांक 31 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अवति:—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 14 के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविधि रखी जाए, अवर्ति:—

“15. श्री वयालार रवि, संसद मवस्य—पत्तन में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिनिधि।”

[फाईल सं० पी टी बी-42/78]
विनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

G.S.R. 510(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoint Shri Vayalar Ravi, M.P., as trustee, representing the labour employed in the Port of Cochin, on the Board of Trustees of the Port of Cochin, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 304(E), dated the 31st March, 1979, namely :—

In the said notification, after Serial Number 14, the following Serial Number and entry shall be inserted, namely :—

“15. Shri Vayalar Ravi, M.P.—Representing the labour employed in the Port”.

[F. No. PTB-42/78]

D. K. JAIN, Joint Secy.

